GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 09 Sep , 2024

Edition: International

Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत स्विस शांति प्रक्रिया में शामिल होने के अपने फैसले की 'समीक्षा' करेगा, राजदूत ने कहा
Page 01 **Syllabus : GS 2 & 3 : सामाजिक न्याय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एमपॉक्स के लक्षणों वाले मरीज को अलग रखा गया
Page 07 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	ग्रहों की सुरक्षा 'विषाक्त एलियंस' को दूर रख रही है
Page 11 **Syllabus : GS 3 : पर्यावरण**	आर्कटिक समुद्री बर्फ के स्तर में परिवर्तन भारत में मानसून के पैटर्न को कैसे बदल सकता है?
समाचार में शब्द	**INDIAsize** पहल
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय - स्वास्थ्य**	नीतिगत पक्षाघात, एक कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र

Page 01 : GS 2 : International relations

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर स्विस शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यूक्रेन द्वारा भारत को प्रोत्साहित किया जा रहा है, हालांकि जून शिखर सम्मेलन से शुरू में भारत ने खुद को अलग कर लिया था।

- यूक्रेन शांति-निर्माण प्रयासों में भारत की सक्रिय भूमिका चाहता है, आगामी चर्चाओं और राजनयिक यात्राओं के माध्यम से इस जुड़ाव को उजागर किया जा रहा है।

Ukraine hopes that India will 'review' its decison on joining the Swiss peace process, says Ambassador

Suhasini Haidar
NEW DELHI

As the Union government looks at a possible role for India in ending the Russia-Ukraine war, Kyiv is keen on getting New Delhi to sign the Swiss peace summit document. After the summit in June, India had issued a statement disassociating itself from its outcome as it did not involve Russia and Ukraine.

Speaking to *The Hindu*, Ukraine's Ambassador to India Oleksandr Polishchuk said that Ukraine President Volodymyr Zelenskyy had proposed a retrospective move by India to join the peace process ahead of plans for a second peace summit in October or November. Ukraine, he said, had more "ambition" for India than playing "post office" between the leaders of the two warring nations.

"We hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to Ukraine and conversations with President Zelenskyy indicate India's support for the peace-building effort," Mr. Polishchuk told *The Hindu*.

He confirmed that Mr. Zelenskyy "discussed the possibility that India could review its decision at the first peace summit in Switzerland, and associate itself with the Burgenstock joint communique", retrospectively or for India to formulate its own proposals that support principles such as humanitarian access and nuclear safety.

> We hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to Ukraine and conversations with President Zelenskyy indicate India's support for the peace-building effort
>
> **OLEKSANDR POLISHCHUK**
> Ukraine's Ambassador to India

"A large democracy like India should not just be a messenger or post office, conveying messages from one country in the conflict to the other – given PM Modi's ability to speak to all sides, he can play a larger role in guiding the process and even in hosting the peace summit," he added.

The envoy's comments come as the Modi government has stepped up its outreach to other countries playing a role in current efforts to end the conflict.

Flurry of visits

External Affairs Minister S. Jaishankar is on a visit to Saudi Arabia, Germany and Switzerland from September 8 to 13 when he will engage Ministers of West Asian nations and heads of UN organisations.

National Security Adviser Ajit Doval will visit Russia from September 10 to 12 for the BRICS NSA meetings where he will meet counterparts from China, Brazil, South Africa, the UAE, Saudi Arabia, Egypt and Ethiopia. The flurry of diplomatic visits comes after Mr. Zelenskyy pitched India as a possible mediator along with other "Global South" countries and Mr. Putin said he valued any efforts by India, China and Brazil on the conflict.

"We need to pay more attention to the implementation of the various plans for cooperation that the leaders agreed to," Mr. Polishchuk said.

स्विस शांति प्रक्रिया:

- स्विस शांति प्रक्रिया का तात्पर्य राजनयिक प्रयासों से है जिसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन संघर्ष को वार्ता और संवाद के माध्यम से हल करना है, जिसमें स्विट्जरलैंड एक तटस्थ आधार के रूप में कार्य करता है।
- जून में शुरू की गई यह प्रक्रिया प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को शामिल करके एक व्यापक शांति समझौते को सुगम बनाने का प्रयास करती है।
- स्विट्जरलैंड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में मानवीय पहुँच और परमाणु सुरक्षा के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाला एक संयुक्त विज्ञप्ति तैयार की गई थी, लेकिन इसमें रूस और यूक्रेन की प्रत्यक्ष भागीदारी शामिल नहीं थी।
- अक्टूबर या नवंबर में होने वाला आगामी दूसरा शिखर सम्मेलन इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें भारत सहित प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ियों से व्यापक समर्थन और प्रस्तावों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।
- लक्ष्य चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: रूस-यूक्रेन युद्ध न केवल इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वर्तमान विश्व व्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। चर्चा करें।

GEO IAS
It's about quality

Page 01 : GS 2 : Social Justice – Health ; GS 3 – Science and Technology

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि हाल ही में सक्रिय एमपॉक्स संक्रमण वाले देश से भारत लौटे एक युवा पुरुष मरीज की पहचान संदिग्ध एमपॉक्स मामले के रूप में की गई है।

- मंत्रालय ने मामले या घटना स्थल के बारे में विवरण जारी नहीं किया, लेकिन कहा कि मरीज को एक निर्दिष्ट अस्पताल में अलग रखा गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई गई है। यह पुष्टि करने के लिए कि उसे एमपॉक्स हुआ है या नहीं, मरीज से नमूने एकत्र किए गए हैं।
- यह दूसरी बार है जब एमपॉक्स को दो साल में यह पदनाम मिला है, 2022 से 116 देशों में 99,000 से अधिक मामले और 208 मौतें दर्ज की गई हैं।

Patient with Mpox symptoms isolated, says Health Ministry

Bindu Shajan Perappadan
NEW DELHI

A young male patient, who recently returned to India from a country with active Mpox transmission, has been identified as a suspected Mpox case, the Union Health Ministry said on Sunday.

The Ministry did not release details about the case or the place of occurrence, but maintained that the patient has been isolated in a designated hospital, where his condition is reported to be stable. Samples have been collected from the patient to confirm whether he has contracted Mpox.

"The development of this case is consistent with the earlier risk assessment

Exercising caution: The government has advised patients to seek medical help if any symptoms are seen. AFP

Centre for Disease Control] NCDC and there is no cause of any undue concern," the Ministry said.

In the Ministry statement, Prashant Joshi, Executive Director of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Nagpur, explained that the

ciated with Mpox can also be confused with other common diseases

Mr. Joshi advised patients to seek medical help if the mentioned symptoms are seen, along with a travel history to endemic areas or contact with a suspected or confirmed case

समाचार का विश्लेषण:

जूनोटिक रोग क्या हैं?

- ये ऐसे संक्रमण हैं जो लोगों और जानवरों के बीच फैलते हैं।

- ये संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे कीटाणुओं के कारण होते हैं।
- कुछ गंभीर और जानलेवा हो सकते हैं, जैसे रेबीज, और अन्य हल्के हो सकते हैं और अपने आप ठीक हो सकते हैं।

एमपॉक्स क्या है?

- एमपॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो एमपॉक्स वायरस (एमपीएक्सवी) के कारण होता है, जिसमें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और चेचक जैसे चकत्ते जैसे लक्षण होते हैं।
- हालांकि आमतौर पर यह अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह कमजोर आबादी, खासकर बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए घातक हो सकता है।
- ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका तक सीमित, यह संक्रमण हाल ही में वैश्विक स्तर पर फैल गया है।

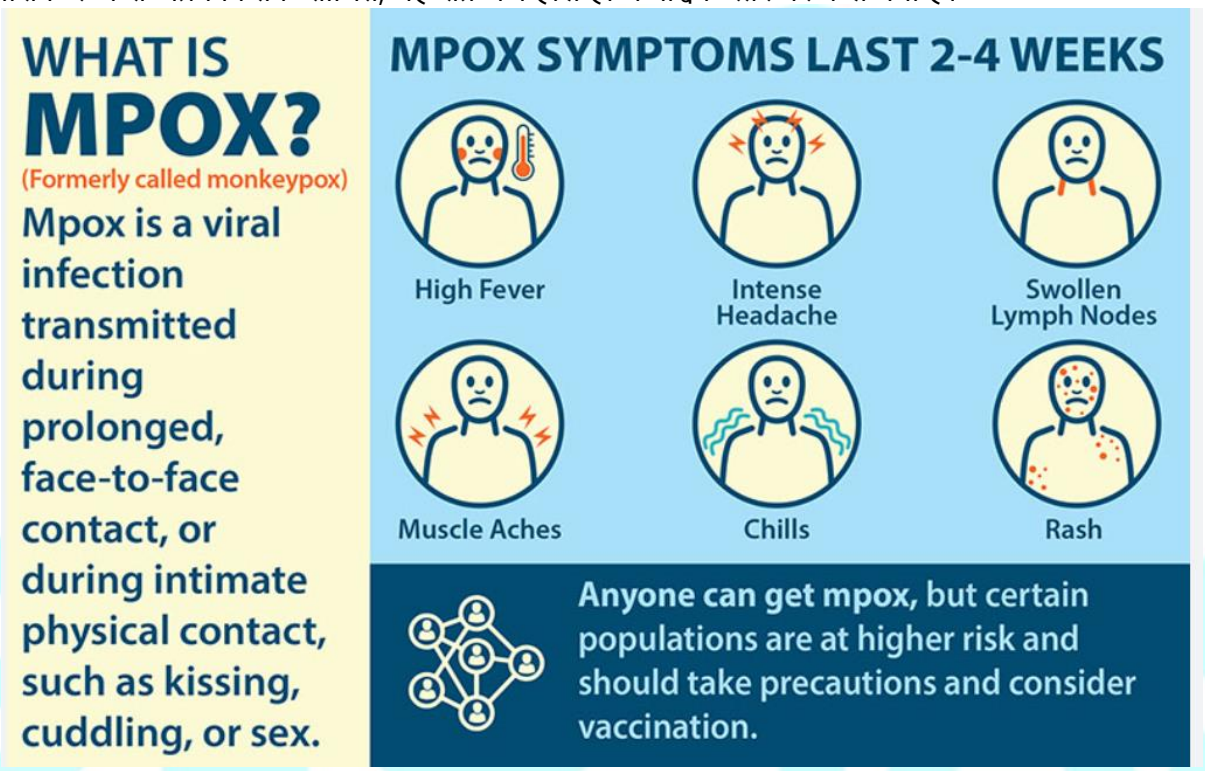

वर्तमान चिंताएँ

- मुख्य चिंता वायरस के अधिक विषैले स्ट्रेन, क्लेड आईबी के प्रसार से उत्पन्न होती है, जो अब मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित हो रहा है - अन्य एमपॉक्स क्लेड्स के साथ देखे जाने वाले पारंपरिक जूनोटिक संचरण से अलग।
- डीआरसी के पड़ोसी देशों में क्लेड आईबी के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसके लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

वैश्विक और भारतीय जोखिम

- इस नए क्लेड के तेजी से फैलने से वैश्विक चिंताएँ पैदा हुई हैं, जिसमें स्वीडन सहित अफ्रीका के बाहर भी मामले सामने आए हैं।
- भारत, जहाँ 2022 के प्रकोप के दौरान मामले देखे गए थे, जोखिम में बना हुआ है, खासकर अंतरराष्ट्रीय यात्रा वायरस के प्रसार का एक कारक है।
- डब्ल्यूएचओ ने 2022 में देखे गए वैश्विक प्रकोप की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

टीके की उपलब्धता

- डब्ल्यूएचओ द्वारा एमपॉक्स के लिए वर्तमान में दो टीकों की सिफारिश की गई है।
- इन टीकों के लिए डब्ल्यूएचओ की हालिया आपातकालीन उपयोग सूची का उद्देश्य विशेष रूप से निम्न-आय वाले देशों में पहुँच में सुधार करना है।
- टीके के वितरण को समन्वित करने और वैश्विक स्तर पर समान पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।
- भारत पिछले प्रकोप के जवाब में टीके और निदान के निर्माण में भी शामिल रहा है।

UPSC Prelims PYQ : 2014

प्रश्न: निम्नलिखित बीमारियों पर विचार करें-

1. डिप्थीरिया

2. चिकनपॉक्स

3. चेचक

उपर्युक्त में से कौन सी बीमारी भारत में समाप्त हो गई है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) 1, 2 और 3

(d) कोई नहीं

उत्तर: b)

GEO IAS It's about quality

Page 07 : Prelims fact

चीन द्वारा अपने तियानवेन-3 मंगल नमूना-वापसी मिशन को 2028 तक आगे बढ़ाने की घोषणा, ग्रह संरक्षण सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों को प्रदूषण से बचाना है।

WHAT IS IT?

Planetary protection: keeping out 'toxic aliens'

Vasudevan Mukunth

In space missions from the earth to another planetary body, planetary protection is the idea that it's important to preserve the biospheres of the earth and the body against contamination by "alien" microbial life.

It's an important principle of interplanetary missions, such as from the earth to the moon or Mars. It stems from the idea that we ought to keep the planetary biosphere "pristine" and from being "corrupted" by influences that may not exist had the space mission not been undertaken.

On September 5, China announced it would be pulling up the date for Tianwen-3, its ambitious Mars sample-return mission, to 2028, potentially ahead of the U.S. During the announcement, the mission's designer said it would abide by the planetary protection principle.

The principle has a legal basis in Article IX of the Outer Space Treaty (1967). It states that parties to the treaty explore outer space while avoiding "harmful contamination and ... adverse changes" in the earth's and the body's environments due to "the introduction of extraterrestrial matter."

An important way to "clean" spacecraft ahead of interplanetary missions to conform to the planetary protection principle is to fully assemble the vehicle and bake it in a dry room for three days at 120 degrees C. This increases the costs and the technical strength of the spacecraft, but such are the demands of keeping biospheres 'clean'.

A model of NASA's Viking 1 lander, which became the first spacecraft to land on Mars in 1976. It was designed and operated to facilitate planetary protection. FILE PHOTO

For feedback and suggestions for 'Science', please write to **science@thehindu.co.in** with the subject 'Daily page'

- यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों द्वारा निर्देशित है और इसमें अंतरिक्ष यान की कठोर नसबंदी शामिल है।

ग्रहीय सुरक्षा सिद्धांत:

- ग्रहीय सुरक्षा से तात्पर्य उन उपायों और सिद्धांतों से है जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों के दौरान पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के जैविक संदूषण को रोकना है।
- यह यह सुनिश्चित करके ग्रहों के वातावरण की अखंडता को संरक्षित करने का प्रयास करता है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर अलौकिक जीवन या अन्य ग्रहों पर पृथ्वी से उत्पन्न जीवन न लाएँ।
- यह सिद्धांत बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) के अनुच्छेद IX द्वारा निर्देशित है, जो यह अनिवार्य करता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण को हानिकारक संदूषण और ग्रहों के वातावरण में प्रतिकूल परिवर्तनों से बचना चाहिए।
- इन मानकों का पालन करने के लिए, अंतरिक्ष यान अंतरग्रहीय मिशनों से पहले सूक्ष्मजीव संदूषण को कम करने के लिए उच्च तापमान पर पकाने जैसी कठोर नसबंदी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं।
- यह प्रक्रिया वैज्ञानिक सटीकता बनाए रखने और अलौकिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

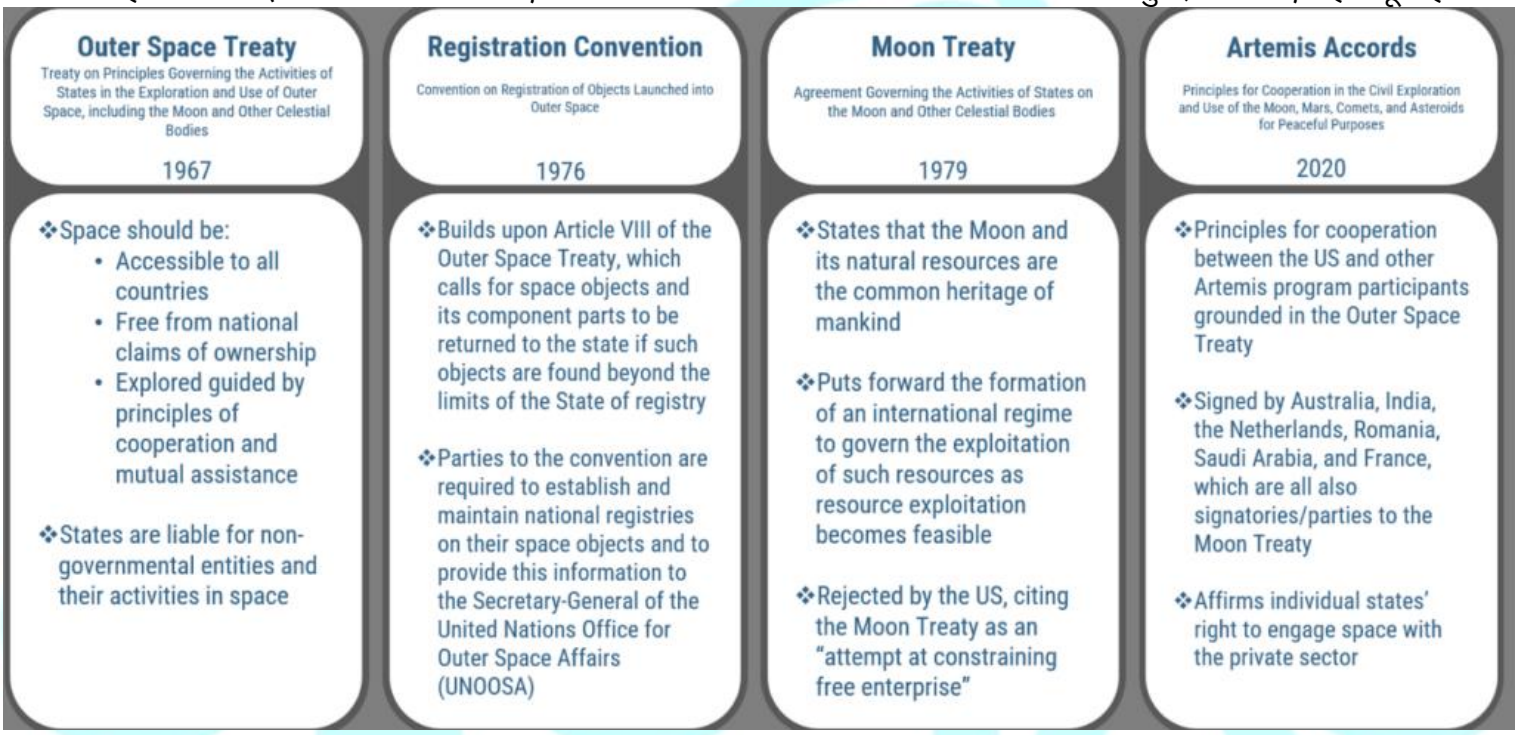

बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)

- तिथि: 27 जनवरी, 1967 को हस्ताक्षरित; 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुई।
- प्रतिभागी: संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहल की गई; बाद में कई अन्य देशों द्वारा अनुसमर्थित।
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के लिए रूपरेखा स्थापित करता है और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।

मुख्य प्रावधान

- गैर-विनियोग: चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष पर किसी भी देश द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है।

- शांतिपूर्ण उपयोग: बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, और अंतरिक्ष गतिविधियों से सभी मानव जाति को लाभ होना चाहिए।
- कोई हथियार नहीं: अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतरिक्ष अन्वेषण और गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

UPSC Prelims PYQ : 2016

प्रश्न: मंगल नमूना वापसी मिशन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान?

1. इसे मंगल ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है

2. इसने भारत को अमेरिका के बाद मंगल की परिक्रमा करने वाला दूसरा देश बना दिया

3. इसने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल की परिक्रमा करने वाला एकमात्र देश बना दिया

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

GEO IAS
It's about quality

Page 11 : GS 3 : Enviroment : Climate Change – Effects of Climate change

इस समाचार में आर्कटिक सागर में घटती बर्फ और भारत के अप्रत्याशित मानसून पैटर्न के बीच संबंध को उजागर करने वाले एक अध्ययन पर चर्चा की गई है।

- इसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ के स्तर में कमी से वायुमंडलीय प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ आती है, जो भारत के मौसम पूर्वानुमान और जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।

Erratic climate: The view from YSR Colony in Vijayawada on September 8. G.N. RAO

How changes in the level of Arctic sea ice can change monsoon patterns in India

Unpredictable, erratic rainfall has become the norm for the Indian monsoon. New research reveals that less sea ice in the central Arctic leads to lower rain in western and peninsular India but more rain in central and northern India

Arkatapa Basu

Yadav, Juhi et al, 'Contrasting response of regional spring Arctic Sea ice variations on Indian summer monsoon rainfall', *Remote Sensing of Environment*, Vol 311, September 1, 2024.

Incessant rainfall has wreaked havoc in India's southeast, leaving at least 17 dead in Andhra Pradesh and thousands homeless and at the mercy of floods in Telangana. The Indian Meteorological Department has also warned of heavy rains in parts of Gujarat, Himachal Pradesh, and Delhi.

Unpredictable, erratic rainfall has become the norm for the Indian monsoon. Once a bringer of relief and hope to the subcontinent, these rains are now a herald of drought and floods.

Climate change is an important reason why. However, a closer look into climate models shows the intricate play of surface temperature, pressure gradients, air currents and even sea ice that is responsible for bringing rain to the Indian landmass. In a study published in the journal *Remote Sensing of Environment* in June, researchers from India's National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR), under the Ministry of Earth Sciences, and South Korea's Korea Polar Research Institute have found that seasonal changes in the Arctic sea ice affect the Indian monsoon as well.

Making of a monsoon

The Indian summer monsoon rainfall (ISMR) over the Indian subcontinent, from July to September, and with most of the rains recorded in July and August, is one of the most prominent monsoon systems in the world.

In summer months, sunlight warms the Central Asian and Indian landmass more and faster than the surrounding ocean. This creates a low pressure band at the Tropic of Cancer called the intertropical convergence zone. Trade winds blowing from the southeast are subsequently deflected towards the Indian landmass due to the Coriolis force and have low pressure after they cross the equator. As they blow over the Arabian Sea, the winds pick up moisture and deposit that as rain over India.

Over the landmass itself, this southwest monsoon splits into two. The Arabian Sea arm brings rain to the west coast while the other arm travels to the Bay of Bengal and brings rain to India's eastern and northeastern parts. The arms finally converge over Punjab and Himachal Pradesh as the Arabian Sea arm moves inward and the Bay of Bengal arm moves along the Himalaya.

The ISMR is much more complex than scientists first anticipated. In the last two decades, climate models have shown that the surface temperatures of the Indian, the Atlantic, and the Pacific Oceans affect the ISMR. The circum-global teleconnection (CGT), a large-scale atmospheric wave flowing at the mid-latitudes, seemed to significantly influence the monsoon as well.

The influence of Arctic sea ice

In recent years, scientists have also suggested that the declining levels of Arctic sea ice, due to climate change, could influence the monsoon's temperament. In the new study, researchers used observational data from 1980 to 2020 and climate models (specifically Coupled Model Intercomparison Project Phases 5 and 6) to check how Arctic sea ice levels affect atmospheric circulations that in turn influence the ISMR.

The results revealed distinct and at times contrasting patterns. According to the paper, less sea ice in the central Arctic leads to lower rain in western and peninsular India but more rain in central and northern India. On the other hand, lower sea ice levels in the upper latitudes, particularly in the Barents-Kara Sea region encompassing the Hudson Bay, the Gulf of St. Lawrence and the Sea of Okhotsk, delay the monsoon's onset and render it more unpredictable.

Several atmospheric systems also influence this pattern. The scientists found that when sea ice levels in the central Arctic increase, the heat transferred from the ocean to the atmosphere triggers a cyclonic circulation at slightly lower latitudes, like in the north Atlantic. This bolsters the Rossby waves, fast-flowing streams of air high in the atmosphere created by the earth's rotation and differences in temperature and weather systems that move west to east. "To put it simply, imagine giant loops in a river of air high above us. These loops can push warm or cold air across the planet and steer storms around, changing weather patterns as they go," Avinash Kumar, an NCPOR scientist and one of the study's co-authors, told *The Hindu*. The enhanced Rossby waves result in high pressure over northwest India and low pressure over the Mediterranean region. This in turn strengthens a narrow, concentrated band of wind, called the Asian jet stream, over the Caspian Sea, causing the subtropical easterly jet – a jet stream blowing over the Indian subcontinent during summer – to shift northward. As a result, an anomalous high pressure region is created over Central Asia, disrupting atmospheric stability over the Indian landmass and bringing more rain over western and peninsular India.

On the other hand, low sea ice over the Barents-Kara Sea region triggers a series of air currents that produce an anomalous high pressure over southwest China. This correlates with a positive Arctic Oscillation – high pressure over the northern Atlantic and Pacific oceans along with a weakening of the CGT, which connects weather events in different parts of the world.

As sea ice levels decrease in the region, heat rises from the Barents-Kara sea, creating an anticyclonic circulation (calm, clear skies) over northwest Europe. This disturbs the upper atmospheric region over subtropical Asia and India.

This instability, coupled with high surface temperature of the Arabian Sea and the moisture picked up from the surrounding water bodies promotes high rainfall over northeastern India while leaving central and northwest regions of the country without much.

Does climate change also play a role?

Now that scientists know a little more about the forces that conspire to bring or withhold rain over India, what can we say about the role of climate change?

"Climate change, by accelerating the reduction of Arctic sea ice, exacerbates the variability and unpredictability of the ISMR," Dr. Kumar said. "Lower Arctic sea ice can lead to more frequent and severe droughts in some regions while causing excessive rainfall and flooding in others."

Apart from highlighting the physical pathways in which the Arctic sea ice affects the Indian monsoon, the current study shows the urgent need to expand research on climate dynamics and for scientists to prepare more accurate forecasts of the ever-changing monsoons.

आर्कटिक समुद्री बर्फ का भारतीय मानसून पर प्रभाव:

भारतीय मानसून का परिचय

- हाल के वर्षों में, अनियमित और अप्रत्याशित वर्षा ने भारतीय मानसून को प्रभावित किया है, जिससे सूखा और बाढ़ आई है।
- जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन कई जलवायु कारकों की जटिल परस्पर क्रिया भी इन परिवर्तनों में योगदान देती है।
- राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) और दक्षिण कोरिया के कोरिया ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान से जूही यादव एट अल द्वारा रिमोट सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ में मौसमी बदलाव भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा (आईएसएमआर) को भी प्रभावित करते हैं।
- विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक समुद्री बर्फ में गिरावट आईएसएमआर को प्रभावित करती है।

भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की यांत्रिकी

- जुलाई से सितंबर तक सक्रिय ISMR दुनिया की सबसे उल्लेखनीय मानसून प्रणालियों में से एक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार है।
- जैसे-जैसे गर्मी के महीने करीब आते हैं, मध्य एशियाई और भारतीय भूभाग आसपास के महासागरों की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होते हैं।
    - o इससे कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जो समुद्र से नमी वाली हवाओं को खींचता है।
    - o दक्षिण-पश्चिम मानसून, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद, दो भागों में विभाजित हो जाता है: एक अरब सागर के माध्यम से भारत के पश्चिमी तट पर बारिश लाता है, जबकि दूसरा बंगाल की खाड़ी से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को प्रभावित करता है।
    - o ISMR प्रणाली शुरू में सोचे गए अनुमान से कहीं अधिक जटिल है, जो समुद्र की सतह के तापमान, दबाव प्रवणता, वायुमंडलीय तरंगों और सर्कम-ग्लोबल टेलीकनेक्शन (CGT), मध्य अक्षांशों में एक तरंग पैटर्न से प्रभावित होती है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **मध्य आर्कटिक समुद्री बर्फ का प्रभाव:**
    - o मध्य आर्कटिक में समुद्री बर्फ की कमी से पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा होती है, लेकिन मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ जाती है।

बैरेंट्स-कारा सागर क्षेत्र का प्रभाव:

- o बैरेंट्स-कारा सागर क्षेत्र में समुद्री बर्फ की कमी से मानसून की शुरुआत में देरी होती है और यह अधिक अप्रत्याशित हो जाता है, जिससे वर्षा पैटर्न प्रभावित होता है।

मानसून के पैटर्न को प्रभावित करने वाली वायुमंडलीय प्रणालियाँ

- **रोस्बी तरंगें और उनका प्रभाव:**

- जब मध्य आर्कटिक में समुद्री बर्फ़ बढ़ती है, तो महासागर से वायुमंडल में गर्मी स्थानांतरित होती है, जिससे निचले अक्षांशों में चक्रवाती परिसंचरण शुरू हो जाता है।
- इससे रॉस्बी तरंगें मजबूत होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। रॉस्बी तरंगें उत्तर-पश्चिम भारत पर उच्च दबाव और भूमध्य सागर पर कम दबाव को बढ़ाती हैं, जिससे भारत पर उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रभावित होता है।
- इसके परिणामस्वरूप मध्य एशिया पर एक असामान्य उच्च दबाव प्रणाली बनती है, जिससे पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में अधिक बारिश होती है।

बैरेंट्स-कारा समुद्री बर्फ़ में कमी:

- बैरेंट्स-कारा क्षेत्र में कम समुद्री बर्फ़ दक्षिण-पश्चिम चीन पर उच्च दबाव को बढ़ाती है और सकारात्मक आर्कटिक दोलन की ओर ले जाती है।
- कम समुद्री बर्फ़ उत्तर-पश्चिम यूरोप पर प्रतिचक्रवाती परिसंचरण की ओर ले जाती है, जिससे उपोष्णकटिबंधीय एशिया और भारत में वायुमंडलीय स्थिरता गड़बड़ा जाती है।
- इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर भारत में अधिक वर्षा होती है, लेकिन मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं।

जलवायु परिवर्तन की भूमिका

- जलवायु परिवर्तन ने आर्कटिक समुद्री बर्फ में कमी को और तीव्र कर दिया है, जिससे ISMR की परिवर्तनशीलता और अप्रत्याशितता और बढ़ गई है।
- जैसे-जैसे समुद्री बर्फ का स्तर गिरता जा रहा है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के साथ-साथ अधिक लगातार और गंभीर सूखे की संभावना है।
- अध्ययन वैश्विक जलवायु प्रणालियों को प्रभावित करने में आर्कटिक समुद्री बर्फ के महत्व को रेखांकित करता है, जिसका भारतीय मानसून पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

- निष्कर्ष आर्कटिक समुद्री बर्फ और भारतीय मानसून के बीच जटिल संबंधों को उजागर करते हैं, यह दर्शाते हैं कि समुद्री बर्फ के नुकसान के प्रभाव कितने दूरगामी हो सकते हैं।
- अध्ययन इन जलवायु गतिशीलता में अधिक व्यापक शोध की आवश्यकता और भविष्य में मानसून परिवर्तनशीलता का अनुमान लगाने के लिए सटीक पूर्वानुमानों की आवश्यकता पर जोर देता है।

UPSC Mains PYQ : 2017

प्रश्न: मानसूनी जलवायु को कौन सी विशेषताएं सौंपी जा सकती हैं जो एशिया में रहने वाली 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को भोजन उपलब्ध कराने में सफल होती है?

Term In News : INDIAsize Initiative

केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने हाल ही में कहा कि सरकार जल्द ही बहुप्रतीक्षित 'इंडियासाइज़' पहल शुरू करेगी।

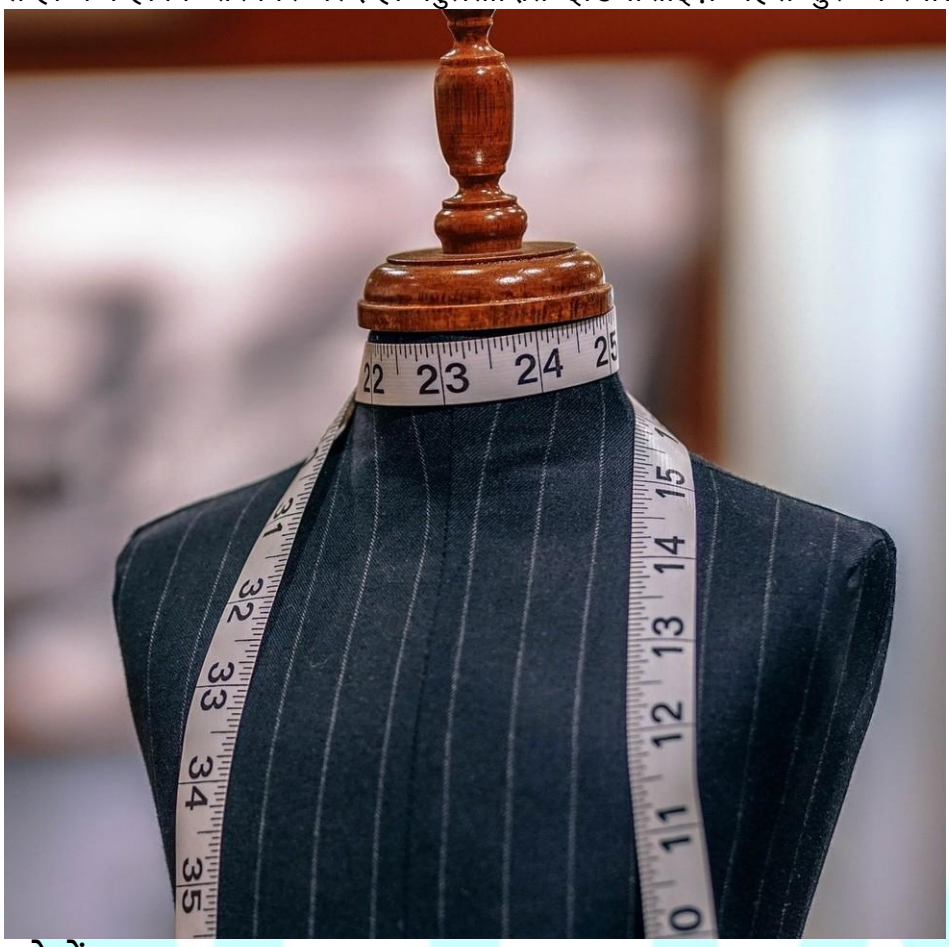

इंडियासाइज़ पहल के बारे में:

- यह कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय शरीर के प्रकारों के लिए बेहतर ढंग से डिज़ाइन किए गए मानकीकृत माप स्थापित करना है।

आवश्यकता:

- वर्तमान में, भारत में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड 'छोटे', 'मध्यम' और 'बड़े' आकार वाले परिधानों के लिए अमेरिका या ब्रिटेन से माप का उपयोग करते हैं।
- हालाँकि, पश्चिमी शरीर के प्रकार ऊँचाई, वजन या शरीर के अंगों के विशिष्ट माप के मामले में भारतीयों से भिन्न होते हैं।
- यह भारतीय शरीर के प्रकारों में विविधता को ध्यान में रखने में विफल रहता है, जिससे अक्सर फिटिंग संबंधी समस्याएँ और उपभोक्ता असंतुष्ट होते हैं।
- वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय परिधान क्षेत्र के लिए मानक शरीर के आकार विकसित करने के लिए इंडियासाइज़ परियोजना को मंजूरी दी ताकि प्रदान किए गए फिट में मौजूदा असमानताओं और विसंगतियों को दूर किया जा सके।

- इस परियोजना में मानव सुरक्षित 3D संपूर्ण शरीर स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच के 25000 (पच्चीस हजार) से अधिक पुरुष और महिला व्यक्तियों से पूरे भारत में मानवशास्त्रीय डेटा एकत्र करना शामिल है।
- निर्मित बॉडी साइज़ चार्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं को ऐसे सामान बनाने में मदद करेगा जो भारतीय बॉडी टाइप के लिए सबसे उपयुक्त हों और अच्छी तरह से फिट होने वाले कपड़ों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखें।
- एक बार शुरू होने के बाद, INDIAsize देश में बिकने वाले भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांडों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा।

GEO IAS
It's about quality

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page: 08 Editorial Analysis

Policy paralysis, a weakened public health sector

Mathew George

Head of the Department of Public Health and Community Medicine, Central University of Kerala, Kasaragod, Kerala

The public health needs of a population are diverse and perception and prioritisation vary across the social strata. Public health policies are those decisions made by the government based on the resources available to address people's health needs. Public health needs include those felt by people (felt needs) based on their lived experiences and those projected upon (projected needs) them by experts – the architects of public health policies. The recent Union Budget has been critiqued for its inadequate focus on the social sector, specifically the public health sector. Public health policies of the government in the last decade indicate that there has been a severe paralysis when it comes to public health policies without any real prescription that addresses the felt needs of people.

Felt needs in public health

Public health needs can be broadly categorised into three groups: First, are the diseases of poverty such as tuberculosis, malaria, undernutrition, maternal death, bouts of illnesses due to food and water-borne infections leading to typhoid, hepatitis, and diarrhoeal diseases faced by the poor and the vulnerable. These problems attain greater significance as attempts to prevent these also pose challenges of addressing livelihood and are non-negotiable from a rights perspective.

Second are the problems of the middle class and those better off on issues that are related to environmental pollution – air, water, waste management, lack of drainage facility and failure to ensure healthy foods and eateries that pose threat to everyday lives, most of which are due to poor infrastructure development and poor market regulations. The list goes on if we add road traffic accidents, climate change and the rise of chronic illnesses. These are also applicable to the first group but may not figure within the hierarchy of priorities.

Third, and the most popular needs in public health, are the curative care needs of a population. Provisioning of curative care is the most critical and controversial policy question in public health. The three levels of curative care envisaged are primary, secondary and tertiary. The poor and the vulnerable rely on primary health-care institutions of the public sector for primary-level care, as it is the most affordable and is closer to their places of residence. Secondary-level care was historically neglected and is still inadequate against population norms. Shortage of infrastructure including health professionals in these facilities aggravates the problem. Tertiary-care needs for curative care among the poor are the focus of the Pradhan Mantri Jan Arogaya Yojana (PMJAY) under Ayushman Bharat.

A history of Indian public health policies in the last decade shows that the National Rural Health Mission, which was started in 2005, and followed by the National Health Mission (NHM) of 2013, were a clear departure from the then existing National Health Policy of 2002, which proposed the commercialisation of health care. It was the NHM's focus on strengthening public sector health care through architectural correction that has revived an otherwise sinking health system after the reform period of the 1990s. Efforts were taken to follow the principles of primary health care while strengthening the institutions of primary health care by implementing the national health programmes through them, thus building goodwill and trust among the people about public sector health care. This was obvious from the health infrastructure available in India, which was reported as 1,53,655 sub centres, 25,308 primary health centres (PHC) and 5,396 community health centres (CHC) as per the rural health statistics, 2015. The impetus created by NHM would have been capitalised had subsequent policies strengthened the secondary- and tertiary-level health care in the public sector. Instead, the focus has shifted entirely on publicly funded health insurance schemes (PFHI) such as the PMJAY under Ayushman Bharat since 2018. PFHI schemes were implemented by the governments of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, and others as an add-on to the overall strengthening efforts under the NHM then.

Primary care is weak while there has been a boost to the growth of the private sector in secondary and tertiary care

Private health care, the real beneficiary

The real beneficiary of PFHI schemes in the Indian context is private sector health care. First, a health insurance cover ideally implies covering all health-care expenses, globally. It is unique that India's health insurance scheme covers only hospitalisation expenses under the scheme. This is based on the market logic that if 50 crore people (12 crore households are the beneficiaries of PMJAY) are enrolled in the scheme; only 2.5 crore people will have an actual need for hospitalisation annually as per epidemiological data.

Further, the outsourcing of secondary and tertiary-care services to the private sector at market rates under the scheme is an open acknowledgement by the government of its failure and a lack of intention to strengthen secondary- and tertiary-level public sector health care in the country. The implication is that the remaining 100 crore population who are not covered under any government schemes are forced to have highly commercialised medical care for their illnesses, incurring an expenditure at market rates. Thus, by monopolising the market for health care, private hospitals pretend to offer services to the government at market rates, at the same time ensuring that the remaining two-thirds of the population must depend on them by making sure that public sector health care is weakened.

The last nail in the coffin of the public health system is the recent transformation of sub centres, PHCs and CHCs into health and wellness centres (HWC) in February 2018. The highlight was to declare that 1,50,000 HWCs were established as new institutions in rural areas, when numbers more than that were already in existence (RHS 2015). The proposal was to have a community health officer, expected to render treatment to a rural population by completing a bridge course. This has transformed the original mandate of sub centres from rendering outreach activity to that which provides curative care. Doctoring gained its acceptance through its act of diagnosis, prognosis, and treatment. Instead, the proposal to equip a community health officer to practise medicine minimally results in the new professional becoming a dignified chemist. The failure to offer curative care in its entirety by any institution will shatter the trust of people in those institutions.

The latest of this was in a 2023 directive to rename all the HWCs (sub centres, PHC and CHC) to 'Ayushman Arogya mandir'. One could not find any clear justifications for this name change. Several questions arise on how this name is of significance to a non-Hindi speaking population. How does the term mandir resonate as the title of a secular health institution?

Threat to public health system

Public health challenges are diverse in a country such as India and there is a need to address these across social groups without fail. For the vulnerable and the poor, prevention programmes and health promotion activities become a luxury when their day-to-day livelihoods are not addressed. It is basic primary- and secondary-level curative care that are their felt needs in public health. Historically, institutions of primary health care were entrusted with this responsibility and were delivering preventive and promotion activities close to their home, by making it culturally and contextually relevant.

The major curative care challenge posed across the country is the loss of trust towards health-care providers (private sector due to commercial interests) and public sector due to overcrowding of health care with inadequate infrastructure due to low provisioning.

The government has slashed the limbs of the public health system by not strengthening secondary- and tertiary-level care in the public sector and instead favouring the growth of the private sector. Finally, the institutions of primary health care – the lifeline of India's public health system – were weakened by projecting them as curative care centres, for popularity and branding, without acknowledging their purpose in health programmes and their interconnections with grassroot-level institutions of health care.

The views expressed are personal

GS Paper 02 : सामाजिक न्याय – स्वास्थ्य

(UPSC CSE (M) GS-2 : 2015) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की सीमाएँ हैं। क्या आपको लगता है कि निजी क्षेत्र इस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है? आप और कौन से व्यवहार्य विकल्प सुझाएँगे? (200 w/12.5m)

UPSC Mains Practice Question भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने से लेकर आयुष्मान भारत जैसी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्राथमिकता देने तक के बदलाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस बदलाव ने कमज़ोर आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और गुणवत्ता को कैसे प्रभावित किया है? (250 w /15 m)

संदर्भ :

- लेख पिछले दशक में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना करता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने से लेकर आयुष्मान भारत जैसी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्राथमिकता देने तक के बदलाव पर प्रकाश डाला गया है।
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पक्ष में इस बदलाव ने प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों को कमजोर कर दिया है और कमजोर आबादी की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताएँ और नीतियाँ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताएँ विविध हैं और सामाजिक स्तरों में भिन्न हैं। इन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नीतियाँ बनाई जाती हैं।
- स्वास्थ्य आवश्यकताएँ या तो महसूस की जाती हैं (आबादी द्वारा अनुभव की जाती हैं) या अनुमानित होती हैं (विशेषज्ञों द्वारा पहचानी जाती हैं)।
- भारत में हाल की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से पिछले दशक में, इन आवश्यकताओं को संबोधित करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई है, विशेष रूप से प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की शुरुआत के बाद।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में महसूस की जाने वाली आवश्यकताएँ

- **गरीबी के रोग:**
  - o गरीब और कमजोर लोग तपेदिक, मलेरिया और कुपोषण जैसी बीमारियों का सामना करते हैं।
  - o इन बीमारियों के लिए निवारक उपाय आवश्यक हैं, लेकिन आजीविका पर उनके प्रभाव के कारण चुनौतीपूर्ण भी हैं।

मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के मुद्दे:

- o पर्यावरण संबंधी चिंताएँ जैसे प्रदूषण (वायु, जल), अपशिष्ट प्रबंधन और उचित बुनियादी ढाँचे की कमी।
- o पुरानी बीमारियों, यातायात दुर्घटनाओं और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि इस समूह की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को और बढ़ा देती है।

उपचारात्मक देखभाल:

- o उपचारात्मक देखभाल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई है।
- o गरीब लोग सस्ती देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों पर निर्भर हैं।
- o माध्यमिक स्तर की देखभाल को ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित किया गया है, और तृतीयक देखभाल वर्तमान में PMJAY द्वारा संबोधित की जाती है।

पिछले दशक में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) (2005) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) (2013) भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में सहायक रहे।
- इन नीतियों का ध्यान प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने, सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वास को बढ़ावा देने और बुनियादी ढाँचे में सुधार करने पर केंद्रित था।
- हालाँकि, यह गति बरकरार नहीं रही और सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत के तहत PMJAY जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ (PFHI)

- मुख्य ध्यान PMJAY जैसी PFHI योजनाओं पर स्थानांतरित हो गया है, जो मुख्य रूप से निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुँचाती हैं।

PFHI के साथ समस्याएँ:

- o यह योजना केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करती है, न कि आउट पेशेंट देखभाल को, जो वैश्विक स्वास्थ्य बीमा मानदंडों से विचलन है।
- o निजी क्षेत्र को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल आउटसोर्स करना सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए सरकार की मंशा की कमी को दर्शाता है।
- o सरकारी योजनाओं के दायरे में न आने वाली अधिकांश आबादी को महंगी, व्यावसायिक निजी स्वास्थ्य सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा का कमज़ोर होना

- **निजी क्षेत्र का प्रभुत्व:**

o निजी अस्पतालों ने सरकारी योजनाओं की आड़ में बाज़ार-दर पर उपचार की पेशकश करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर एकाधिकार कर लिया है।
o इस प्रथा ने सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा, विशेष रूप से द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सेवाओं को और कमज़ोर कर दिया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का रूपांतरण:

o 2018 में, उप-केंद्रों, PHCs और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) में बदल दिया गया।
o 2015 के आंकड़ों के अनुसार, इन HWCs को अब नए संस्थानों के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जबकि पहले से ही ऐसी ही सुविधाएँ मौजूद हैं।
o इन केंद्रों पर न्यूनतम प्रशिक्षण वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रखने की पहल उनके मूल उद्देश्य को कमज़ोर करती है, जिससे वे न्यूनतम उपचारात्मक देखभाल प्रदाता बन जाते हैं।
o अपर्याप्त उपचारात्मक देखभाल और अत्यधिक तनाव वाले बुनियादी ढाँचे के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में विश्वास कम होता जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सामने चुनौतियाँ

- भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, और महसूस की जाने वाली ज़रूरतें अक्सर अनदेखी की जाती हैं।
- गरीबों के लिए, बुनियादी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की देखभाल ज़रूरी है।
- ऐतिहासिक रूप से, PHCs जैसी संस्थाएँ ये सेवाएँ और निवारक उपाय प्रदान करती थीं, लेकिन उनके कमज़ोर होने से स्वास्थ्य सेवा वितरण में अंतर पैदा हो गया है।

विश्वास का नुकसान:

o निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक हितों और सार्वजनिक क्षेत्र की भीड़भाड़ वाली सुविधाओं के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में विश्वास का नुकसान हुआ है।
o सार्वजनिक क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में विफलता ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है।

निष्कर्ष

- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान, जो कभी भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आधारशिला थे, उन्हें निवारक देखभाल में उनके मूल उद्देश्य को स्वीकार किए बिना उपचारात्मक देखभाल केंद्रों में बदलकर कमज़ोर कर दिया गया है।
- इसके परिणामस्वरूप भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भविष्य के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है, क्योंकि कमज़ोर आबादी की बुनियादी ज़रूरतें अभी भी अनसुलझी हैं।